VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

Class 12 commerce Sub. ECO/B Date 12.05.2021

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

INDIAN ECONOMY ON THE EVE OF INDEPENDENCE(R.Notes)

Feature of Indian economy on the eve of independence:

- 1. **Stagnant economy**: There was very slow or no economic growth in the country. As a result of stagnation, there was unemployment, death, and suffering due to lack of food.
- **2. Backward economy**: Indian economy was a backward and per capita income was very low and in India, it was just Rs. 230 from 1947-1948.
- **3. Agricultural backwardness**: With 70% of people engaged in agriculture, its contribution to GDP was only 50%. Productivity and production too were extremely low.
- 4. **Industrial backwardness**: Industrial sector was not developed, there was a lack of basic and heavy industries in the country.
- **5. Widespread Poverty:** The people in the country could not even meet their basic needs i.e food, shelter and clothing. Unemployment and Illiteracy were other issues faced by the country.
- **6. Poor Infrastructure**: Infrastructure like communication, transport, power or energy was underdeveloped.
- **7. Major dependence on imports:** As a result of industrial backwardness in the country several consumer goods like medicines were imported from abroad.
- **8. Limited Urbanisation:** Majority of the population lived in villages meaning that they lacked opportunities outside agriculture.
- **9. Colonial economy**: As India was a British colony, Britishers exploited Indian economy for their own benefits.

AGRICULTURE ON THE EVE OF INDEPENDENCE

1.Low Production and Productivity:

Production refers to the total output and Productivity refers to output per hectare hand, both were very low at the time of Independence.

- **2. High Degree of Uncertainty**: Agriculture in India was heavily dependent on the rainfall, due to the lack of permanent means of irrigation(dams, wells) and no efforts by Britishers were made to strengthen the agricultural sector.
- 3. The dominance of Subsistence Farming: Subsistence farming means the farming that is done just to meet the basic needs of the farmer (and his family). In India, subsistence-based farming was done resulting in little or no surplus left for sale meaning that there was a lack of commercial outlook. This lead to the backwardness of the agricultural sector and the nation.
- **4. Difference/Gulf between the Owners of the Soil and the Tillers of the Soil:** The owners of the soil shared the output with the tillers but they did not share the cost of production. The owners were simply interested in increasing their income in terms of share of output. For tillers agriculture was a source of subsistence and for the owners, it

was a source of income without investment creating a wide economical gap between two.

5. Small and Fragmented Holdings: There were small and fragmented landholdings leading to low output at a high cost of production, therefore, landholdings were uneconomical.

6. Zamindari System or Land Revenue System under the British Raj:

During the British Rule, a unique land revenue system was introduced in India. Under this system, a triangular relationship was set up between the government, the owners and the tillers of the soil.

This system was called "The Zamindari System". Features of the Zamindari system are as follows:

- i) Zamindars were recognized as the permanent owners of the soil.
- ii) Zamindars had to pay fixed sum or revenue to the government as land revenue and if they were unable to do so they stood in danger of losing their rights.
- iii) Zamindars were free to extract as much as they want from the tillers of the soil as they wished and could.

Problems with the Zamindari System:

- i) Unlimited exploitation of the tillers of the soil by the zamindars.
- ii) High rates of land revenue to be paid by tillers.
- iii) Tillers were reduced to the status of landless laborers resulting in earning just to meet the basic needs.

7. Forced Commercialisation of Agriculture:

Commercialization meant that there was Shift from cultivation for:

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता:

- 1. स्थिर अर्थव्यवस्था: देश में बहुत धीमी या कोई आर्थिक वृद्धि नहीं थी। ठहराव के परिणामस्वरूप, भोजन की कमी के कारण बेरोजगारी, मृत्यु और पीड़ा थी।
- 2. पिछड़ी अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई थी और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी और भारत में यह सिर्फ रु। 1947-1948 से 230।
- 3. कृषि पिछड़ापन: 70% लोग कृषि में लगे हुए हैं, जीडीपी में इसका योगदान केवल 50% था। उत्पादकता और उत्पादन भी बह्त कम थे।
- 4. औद्योगिक पिछड़ापन: औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं था, देश में बुनियादी और भारी उद्योगों की कमी थी।

- 5. व्यापक गरीबी: देश में लोग अपनी बुनियादी जरूरतों यानी भोजन, आश्रय और कपड़ों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी और निरक्षरता देश द्वारा सामना किए जाने वाले अन्य मृद्दे थे।
- 6. खराब बुनियादी ढांचा: संचार, परिवहन, बिजली या ऊर्जा जैसे बुनियादी ढांचे को अविकसित किया गया था।
- 7. आयात पर प्रमुख निर्भरता: देश में औद्योगिक पिछड़ेपन के परिणामस्वरूप कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे दवाइयां विदेशों से आयात की गईं।
- 8. सीमित शहरीकरण: आबादी का अधिकांश हिस्सा गांवों में रहता था जिसका अर्थ है कि उनके पास कृषि के बाहर अवसरों की कमी थी।
- 9. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था: जैसा कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिशों ने अपने लाभ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया।

स्वतंत्रता की पूर्व कृषि

1. कम उत्पादन और उत्पादकता:

उत्पादन कुल उत्पादन को दर्शाता है और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादन को संदर्भित करता है, दोनों स्वतंत्रता के समय बह्त कम थे।

- 2. अनिश्चितता की उच्च डिग्री: सिंचाई के स्थायी साधनों (बांधों, कुओं) की कमी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर थी।
- 3. सब्सिडी खेती का वर्चस्व: सब्सिडी की खेती का अर्थ है वह खेती जो किसान (और उसके परिवार) की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। भारत में, निर्वाह-आधारित खेती की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए बहुत कम या कोई अधिशेष नहीं बचा था जिसका अर्थ था कि व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी थी। इससे कृषि क्षेत्र और देश का पिछड़ापन दूर होता है।
- 4. मिट्टी के मालिकों के बीच अंतर / खाड़ी और मिट्टी के टिलर: मिट्टी के मालिकों ने टिलर के साथ उत्पादन को साझा किया लेकिन उन्होंने उत्पादन की लागत को साझा नहीं किया। मालिकों को केवल

उत्पादन की हिस्सेदारी के मामले में अपनी आय बढ़ाने में रुचि थी। टिलर के लिए कृषि निर्वाह का एक स्रोत था और मालिकों के लिए, यह निवेश के बिना आय का एक स्रोत था जो दो के बीच एक व्यापक आर्थिक खाई पैदा करता था।

- 5. छोटे और खंडित होल्डिंग्स: छोटे और खंडित लैंडहोल्डिंग थे, जो उत्पादन की उच्च लागत पर कम उत्पादन के लिए अग्रणी थे, इसलिए, लैंडहोल्डिंग गैर-आर्थिक थे।
- 6. ब्रिटिश राज के तहत जमींदारी प्रणाली या भूमि राजस्व प्रणाली:

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में एक अद्वितीय भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत, सरकार, मालिकों और मिट्टी के टिलरों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया था।

इस प्रणाली को "जमींदारी प्रणाली" कहा जाता था। जमींदारी प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i) जमींदारों को मिट्टी के स्थायी मालिक के रूप में मान्यता दी गई थी।
- ii) जमींदारों को सरकार को भूमि राजस्व के रूप में निश्चित राशि या राजस्व का भुगतान करना पड़ता था और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ थे, तो वे अपने अधिकारों को खोने के खतरे में थे।
- iii) जमींदार अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी के टिलर से जितना चाहें उतनी मात्रा में निकालने के लिए स्वतंत्र थे।

जमींदारी प्रणाली के साथ समस्याएं:

- i) जमींदारों दवारा मिट्टी के टिलर का असीमित शोषण।
- ii) भू-राजस्व की उच्च दरों का भुगतान टिलर द्वारा किया जाना है।
- iii) भूमिहीन मजदूरों की स्थिति तक टिलर कम हो गए, जिसके परिणामस्वरूप सिर्फ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाई हुई।
- 7. कृषि का जबरन व्यावसायीकरण:

व्यावसायीकरण का मतलब यह था कि इसके लिए खेती से बदलाव किया गया था: